SHRINKING SUBSCRIBERS: THE MIB-TRAI DTH DEADLOCK

As India's DTH sector faces an existential crunch, industry stakeholders express growing frustration over Ministry of Information and Broadcasting's inaction on TRAI's license fee reform — raising broader questions on regulatory coordination and market fairness.

Nearly two years have passed since the Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) recommended slashing the licensing fee for Direct-to-Home (DTH) operators from 8% to 3% of their Adjusted Gross Revenue (AGR). Yet, the Ministry of Information and Broadcasting (MIB) remains mute, keeping the industry in a regulatory limbo at a time when financial pressures are mounting and subscriber numbers are steadily declining.

India's four private DTH players — Tata Play, Bharti Telemedia, Dish TV, and Sun Direct — are caught in the crossfire. Subscriber numbers have dropped sharply by nearly 11 million since 2021, a decline fueled by rapid OTT adoption and the expanding footprint of Prasar Bharati's DD Free Dish, the free-to-air satellite platform. Against this backdrop, the delayed implementation of TRAI's recommendations threatens not just profitability but the sector's long-term viability.

THE TRAI PROPOSAL: A LIFELINE ON HOLD

In August 2023, TRAI submitted its "Recommendations on License Fee and Policy Matters of DTH Services," proposing a phased reduction of the license fee to 3% of AGR by FY 2027, eventually aiming to eliminate it altogether. This move was designed to give DTH operators a fighting chance in a market increasingly skewed by free-to-air services and OTT platforms.

Despite clear industry support, MIB has yet to act. "We have done our part; it is now up to the ministry to take the next steps," said a senior TRAI official, speaking on

घटते ग्राहकः एमआईबी–ट्राई डीटीएच गतिरोध

भारत का डीटीएच क्षेत्र के अस्तित्व के संकट से जूझने के साथ ही उद्योग के हितधारक ट्राई के लाइसेंस शुल्क सुधार पर सूचना व प्रसारण मंत्रालय की निष्क्रियता पर बढ़ती निराशा व्यक्त कर रहे हैं–जिससे विनियामक समन्वय और बाजार निष्पक्षता पर व्यापक सवाल उठ रहे हैं।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा डॉयरेक्ट–टू–होम (डीटीएच) ऑपरेटरो के लिए लाइसेंस शुल्क को उनके समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के 8% से घटाकर 3% करने की सिफारिश किये हुए लगभग दो साल बीत चुके हैं। फिर भी सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) चुप है जिससे उद्योग को ऐसे समय में नियामक अधर में लटकाये रखा जा रहा है जब वित्तीय दबाव बढ़ रहे हैं और ग्राहकों की संख्या में गिरावट आ रही है।

भारत के चार निजी डीटीएच प्लेयर्स–टाटा प्ले, भारती टेलीमीडिया, डिश टीवी और सन डॉयरेक्ट–क्रॉसफायर में फंस गये हैं। 2021 से सब्सक्राइबरों की संख्या में 11 मिलियन की भारी गिरावट आयी है, यह गिरावट ओटीटी को तेजी से अपनाने और प्रसार भारती के डीडी फ्रीडिश, फ्री–टू–एयर सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के बढ़ते प्रभाव के कारण हुई है। इस पृष्ठभूमि में ट्राई की सिफारिशों के विलंबित कार्यान्वयन से न केवल लाभप्रदता बल्कि सेक्टर की दीर्घकालिक व्यवहार्यता को भी खतरा है।

ट्राई का प्रस्तवः रूकी हुई जीवनरेखा

अगस्त 2023 में ट्राई ने 'डीटीएच सेवाओं के लाइसेंस शुल्क और नीतिगत मामलों पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कीं, जिसमें वित्तवर्ष 2027 तक लाइसेंस शुल्क को चरणवद्ध तरीके से घटाकर एजीआर का 3% करने का प्रस्ताव था, जिसका उद्देश्य अंततः इसको पूरी तरह से समाप्त करना था। यह कदम डीटीएच ऑपरेटरों को फ्री–टू–एयर सेवाओं और ओटीटी प्लेटफॉर्मों द्वारा तेजी से बढ़ते बाजार में लड़ने का मौका देने के लिए बनाया गया था।

उद्योग जगत के स्पष्ट समर्थन के बावजूद एमआईवी ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। नाम न बताने की शर्त पर ट्राई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा 'हमने अपना काम कर दिया है, अब अगला कदम

condition of anonymity. The prolonged delay has frustrated operators who continue to pay the higher 8% fee amid shrinking revenues.

MARKET REALITIES: DECLINING SUBSCRIBERS, RISING COSTS

TRAI's latest data paints a stark picture: the combined subscriber base fell from 69.57 million in March 2021 to 58.22 million in December 2024. Tata Play leads with a 31.49% market share, followed by Bharti Telemedia (29.89%), Sun Direct (19.5%), and Dish TV (19.13%).

The dual onslaught of OTT growth and DD Free Dish's rural penetration is eroding traditional pay-TV revenue. "Operating under an 8% license fee when the regulator has recommended a cut to 3% is like a penalty on survival," said Rajesh Verma, CEO of a leading DTH operator.

Adding to the burden, MIB has recently issued license fee demands exceeding Rs. 16,000 crore, worsening cash flow pressures and threatening investments in customer experience and technology upgrades.

Industry analysts believe MIB is weighing the broader implications of fee reductions within the wider broadcast ecosystem. While DTH operators pay roughly Rs. 20 crore annually in satellite transponder fees, cable multi-system operators (MSOs) incur substantially higher operational costs — with leased line fees exceeding Rs. 80 crore yearly, plus hefty right-of-way charges.

उठाना मंत्रालय पर निर्भर है।'लंबे समय से हो रही देरी से ऑपरेटर निराश हैं, जो घटते राजस्व के बीच 8% से अधिक शुल्क का भुगतान करना जारी रखते हैं।

बाजार की हकीकतः घटते ग्राहक, बढ़ती लागत

ट्राई के नवीनतम डेटा एक स्पष्ट तस्वीर पेश करते हैंः संयुक्त ग्राहक आधार मार्च 2021 में 69.57 मिलियन से दिसंबर 2024 में 58.22 मिलियन तक गिर गया। टाटा प्ले 31.49% बाजर हिस्सेदारी के साथ सबसे आगे है, उसके बाद भारती टेलीमीडिया (29.89%), सन डॉयरेक्ट (19.5%) और डिश टीवी (19.13%) है।

ओटीटी विकास और डीडी फ्रीडिश के ग्रामीण क्षेत्रों में पैठ के दोहरे हमले से पारंपरिक पे-टीवी राजस्व में कमी आ रही है। एक प्रमुख डीटीएच ऑपरेटर के सीईओ राजेश वर्मा ने कहा, 'जब नियामक ने 3% तक की कटौती की सिफारिश की है, तो 8% लाइसेंस शुल्क के तहत काम करना अस्तित्व पर जुर्माना लगाने जैसा है।'

बोझ को और बढ़ाते हुए एमआईबी ने हालही में 16,000 करोड़ रुपये से अधिक की लाइसेंस फीस की मांग जारी की है, जिससे नकदी प्रवाह का दबाव और बिगड़ गया है और ग्राहक अनुभव और प्रौद्योगिकी अपडेट में निवेश का खतरा है।

उद्योग विश्लेषकों का मानना है कि एमआईबी व्यापक प्रसारण पारिस्थितिकीतंत्र के भीतर शुल्क की कटौती के व्यापक प्रभावों पर विचार कर रहा है। जबकि डीटीएच ऑपरेटर सैटेलाइट ट्रांसपोंडर शुल्क के रूप में सालाना 20 करोड़ रुपये का भुगतान करते हैं, केबल मल्टी सिस्टम ऑपरेटर को काफी अधिक परिचालन लागत का सामना करना पड़ता है– लीज्ड लाइन शुल्क सालाना 80 करोड़ रुपये से अधिक है, साथ ही भारी राइट ऑफ वे शुल्क भी है।

"There is a fear that license fee relief for DTH might skew competition unfairly against cable operators, disrupting the overall ecosystem balance," explained Anjali Menon, a senior media policy analyst.

Additionally, legal entanglements and unclear jurisdictional boundaries between TRAI (which regulates telecom and broadcast) and MIB (which finalizes policy) may be causing inertia. The industry remains uncertain about who is ultimately accountable for driving reform.

THE ROAD AHEAD: A CALL FOR CLARITY AND COORDINATION

Without decisive intervention from MIB, the DTH sector risks further contraction. Players may be forced to hike consumer prices, consolidate, or reduce services—outcomes that could undermine millions of households still reliant on pay TV.

The resolution rests on transparent, coordinated policy action that balances the needs of DTH operators, cable MSOs, and emerging platforms, while preserving fair competition and consumer choice.

As the market continues to evolve at breakneck speed, stakeholders urge the government to align regulatory frameworks with ground realities — ensuring that India's broadcast ecosystem remains vibrant, competitive, and future-ready.

DTH Subscriber Base Decline (March 2021 – Dec 2024)

- March 2021: 69.57 million
- March 2024: 61.97 million
- Sept 2024: 59.91 million
- Dec 2024: 58.22 million

Market Share of Major DTH Operators (December 2024)

- Tata Play: 31.49%
- Bharti Telemedia: 29.89%
- Sun Direct: 19.5%
- Dish TV: 19.13% ■

वरिष्ठ मीडिया नीति विश्लेषक अंजलि मेनन ने बताया कि 'डर इस बात का है कि डीटीएच में लाइसेंस शुल्क में छूट केबल ऑपरेटरों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा को गलत तरीके से प्रभावित कर सकती है, जिससे समग्र पारिस्थितिकीतंत्र संतुलन बिगड़ सकता है।

इसके अतिरिक्त ट्राई (जो दूरसंचार और प्रसारण को नियंत्रित करता है) और एमआईबी (जो नीति को अंतिम रूप देता है) के बीच कानूनी उलझने और अस्पष्ट अधिकार क्षेत्र की सीमायें जड़ता का कारण बन सकती हैं। उद्योग इस बात को लेकर अनिश्चित है कि सुधार को आगे बढ़ाने के लिए आखिरकार कौन जिम्मेदार है।

आगे की राहः स्पष्टता और समन्वय के लिए आह्वान

एमआईबी के निर्णायक हस्तक्षेप के बिना डीटीएच क्षेत्र में और संकुछन का जोखिम है। खिलाड़ियों को उपभोक्ता कीमतों में वृद्धि करने, सेवाओं को समेकित करने या कम करने के लिए मजबूर किया जा सकता है–ऐसे परिणाम जो अभी भी पे टीवी पर निर्भर लाखों परिवारों को कमजोर कर सकते हैं।

यह संकल्प पारदर्शी, समन्वित नीतिगत कार्रवाई पर आधारित है जो निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता की पसंद को बनाये रखते हुए डीटीएच ऑपरेटरों, केबल एमएसओ और उभरते प्लेटफार्मो की जरूरतों को संतुलित करता है।

चूंकि बाजार तेजी से विकसित हो रहा है, इसलिए हितधारकों ने सरकार से नियामक ढ़ांचे को जमीनी हकीकत के साथ जोड़ने का आग्रह किया है–यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत का प्रसारण पारिस्थितिकीतंत्र जीवंत, और भविष्य के लिए तैयार रहे।

डीटीएच सब्सक्राइबर में गिरावट (मार्च 2021 – दिसंबर 2024)

- मार्च 2021ः 69.57 मिलियन
- मार्च 2024ः 61.97 मिलियन
- सितंबर 2024ः 59.91 मिलियन
- दिसंबर 2024ः 58.22 मिलियन

प्रमुख डीटीएच ऑपरेटरों की बाजार हिस्सेदारी (दिसंबर 2024)

- टाटाप्लेः 31.49%
- भारती टेलीमीडियाः 29.89%
- सनडॉयरेक्टः 19.5%
- डिश टीवीः 19.13% ■

LICENSE FEE COMPARISON AND COSTS
लाइसेंस शुल्क तुलना और लागत

Category श्रेणी	License Fee % of AGR एजीआर का लाइसेंस शुल्क %	Annual Transponder/Operational Cost वार्षिक ट्रांसपोंडर/संचालन लागत
DTH Operators डीटीएच ऑपरेटर्स	**8% (proposed 3%)** 8% (प्रस्तावित 3%)	**Rs. 20 crore (transponder fees)** 20 करोड़ रु (ट्रांसपोंडर शुल्क)
Cable MSOs केबल एमएसओ	**NA** **NA**	**Rs. 80+ crore (leased lines + RoW)** 80+ करोड़ रु (लीज्ड लाइन्स + आरओडब्लू)